



गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15

अंक : 180

दि. 01.11.2025,

शनिवार

पाना : 04

किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKALAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

सरकार खुलकर खर्च कर रही है, 4 महीने में 70% बड़ा राजकोषीय घाटा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोरदार निवेश

(जीएनएस)। नई दिल्ली। केंद्र सरकार विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए खुलकर खर्च कर रही है, जिसका सीधा असर देश के राजकोषीय घाटे पर दिखने लगा है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के पहले चार महीनों यानी अप्रैल से जुलाई के बीच राजकोषीय घाटा 70% तक उछलकर 4.68 लाख करोड़ पहुंच गया है। यह पूरे साल के बजटीय अनुमान का लगभग 29.9% है। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 2.77 लाख करोड़ था।



केंद्र सरकार के अकाउंट्स (CGA) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस तेजी की सबसे बड़ी वजह पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) में 31% की भारी वृद्धि है। सरकार ने इस अवधि में 3.47 लाख करोड़ का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक परियोजनाओं में किया, जबकि पिछले साल यह खर्च 2.61 लाख करोड़ था। सरकार का मानना है कि यह खर्च देश की विकास गति को बनाए रखने और रोजगार सृजन के लिए जरूरी है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी के 4.4% पर रखा है, जो पिछले वर्ष के 4.8% से कम है। लेकिन शुरुआती चार महीनों के आंकड़े बताते हैं कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वित्तीय अनुशासन और राजस्व सुधार की बड़ी चुनौती बनी हुई है। राजस्व प्राप्ति और कुल खर्च की स्थिति सरकार का कुल खर्च इस अवधि में 13 लाख करोड़ से बढ़कर 15.64 लाख करोड़ हो गया है, जो पूरे साल के लक्ष्य का 31% है। वहीं टैक्स से शुद्ध कमाई में गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल-जुलाई के बीच नेट टैक्स रेवेन्यू 6.62 लाख करोड़ रहा, जो पिछले साल 7.15 लाख करोड़ था। टैक्स फाइलिंग की समय सीमा बढ़ने से इस कमी का कुछ असर देखने को मिला है। गैर-कर राजस्व (नॉन-टैक्स रेवेन्यू) 4.03 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो लक्ष्य का 69.2% है। कुल राजस्व प्राप्ति 10.95 लाख करोड़ रही, जो वार्षिक लक्ष्य का 31.3% है। सॉब्सिडी के मोर्चे पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। मुख्य सॉब्सिडियों पर खर्च पिछले साल के 1.26 लाख करोड़ से घटकर 1.14 लाख करोड़ रह गया है, जो वित्तीय अनुशासन की दिशा में सकारात्मक संकेत देता है। कैपिटल स्पेंडिंग से घाटा बढ़ा, पर विकास को मिल रही रफ्तार समीक्षाधीन अवधि में केंद्र सरकार का कुल व्यय 23 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो बजट अनुमान का 45.5% है। इसमें 17.22 लाख करोड़ राजस्व

जहाजों पर सैन्य हमला अस्वीकार्य, अमेरिका पर संयुक्त राष्ट्र का कड़ा प्रहार, जांच की उठी मांग

(जीएनएस)। जिनेवा। संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि दक्षिण अमेरिकी समुद्री क्षेत्र में ड्रग्स की तस्करी के नाम पर जहाजों पर किए जा रहे सैन्य हमले "अस्वीकार्य और गैरकानूनी" हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन ने इन घटनाओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता रवीना शमदासानी ने जिनेवा में बताया कि मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने इन हमलों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा, "पिछले दो महीनों में अमेरिकी नौसेना और वायुसेना द्वारा किए गए हमलों में 60 से अधिक लोगों की मौत हुई है। इन मृतकों में कई निर्दोष नागरिक भी शामिल हैं, जो किसी भी दृष्टि से स्वीकार्य नहीं हैं।" टर्क ने चेतावनी दी कि यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों और समुद्री संधियों का गंभीर उल्लंघन प्रतीत होती है। उनके अनुसार, "किसी देश को यह अधिकार नहीं है कि वह संप्रभु जलक्षेत्रों के बाहर ऐसी घातक कार्रवाई करे, जो निरदोषों की जान ले। ड्रग्स या अवैध व्यापार से निपटने के लिए हवाई हमले नहीं, बल्कि कानूनी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है।" संयुक्त राष्ट्र के इस बयान के बाद वैश्विक स्तर पर बरस छिड़ गई है, क्योंकि यह पहली बार है जब संयुक्त राष्ट्र के किसी संगठन ने सार्वजनिक रूप से अमेरिका की सैन्य नीति की खुलकर आलोचना की है। दूसरी ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में इन कार्रवाइयों का बचाव करते हुए कहा कि "अमेरिका किसी निर्दोष को निशाना नहीं बना रहा, बल्कि ड्रग्स माफिया और तस्करो के नेटवर्क को खत्म करने के लिए निर्णायक कदम उठा रहा है।" ट्रंप ने यह भी कहा कि ड्रग्स से संबंधित गतिविधियाँ अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी हैं, और उनके खिलाफ "कठोर कार्रवाई" जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख टर्क ने कहा, "ड्रग्स या आतंकवाद से लड़ाई केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों के दायरे में रहनी चाहिए। किसी भी देश को मानवाधिकारों की अहंता करना सैन्य अभियान चलाने का अधिकार नहीं है। ऐसे हमले न केवल अंतरराष्ट्रीय स्थिरता को खतरे में डालते हैं, बल्कि निर्दोष जीवन को भी जोखिम में डालते हैं।" उन्होंने अमेरिकी प्रशासन से अपील की कि वह इन सैन्य कार्रवाइयों को तत्काल रोके, जवाबदेही तय करे, और मृतकों के परिवारों को न्याय दिलाए। विश्लेषकों का कहना है कि यह विवाद आने वाले समय में अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के संबंधों में तनाव बढ़ा सकता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की यह आलोचना अमेरिकी वैश्विक नीति पर एक राजनयिक दबाव के रूप में देखी जा रही है।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने युद्धविराम जारी रखने पर सहमति जताई, कतर और तुर्किये की मध्यस्थता से बनी बात

(जीएनएस)। अंकारा (तुर्किये)। दक्षिण एशिया के अशांत सीमाई क्षेत्र से एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने लंबे तनाव और सीमा झड़पों के बाद युद्धविराम जारी रखने पर सहमति जताई है। यह समझौता तुर्किये और कतर की मध्यस्थता से हुआ है, जिसने दोनों पड़ोसी देशों को एक बार फिर संवाद की राह पर ला दिया है। तुर्किये के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार सुबह एकस (पूर्व दिव्य) पर जारी संयुक्त बयान में कहा कि "दोनों देशों ने आपसी समान और क्षेत्रीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए युद्धविराम जारी रखने और आगे के लिए स्पष्ट तंत्र बनाने पर सहमति जताई है।" सूत्रों के मुताबिक, इस्तांबुल में बोते शनिवार से चल रही शांति वार्ता शुरुआत में असफल होती दिख रही थी, लेकिन कतर और तुर्किये के राजनयिकों की लगातार कोशिशों के बाद वार्ता में फिर प्रगति हुई। बातचीत के दौरान सबसे बड़ी सफलता यह रही कि दोनों पक्षों ने 'निगरानी एवं सत्यापन तंत्र' (Monitoring and Verification Mechanism) बनाने पर सहमति जताई, जो युद्धविराम के उल्लंघन की स्थिति में जांच करेगा और जिम्मेदारी तय करेगा। संयुक्त बयान में कहा गया है कि अगली बैठक 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगी, जिसमें युद्धविराम को लागू करने की

हिंद महासागर में चीन की हलचल पर नौसेना की पैनी नजर

(जीएनएस)। नई दिल्ली। हिंद महासागर में बढ़ती चीन की सैन्य गतिविधियों के बीच भारतीय नौसेना ने स्पष्ट कर दिया है कि वह पूरी तरह चौकस है और किसी भी प्रकार की उकसाने वाली कार्रवाई का जवाब देने में सक्षम है। नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने शुक्रवार को कहा कि "ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। नौसेना की तैनाती पूरी तरह सक्रिय है, और किसी भी स्थिति में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।"

वाइस एडमिरल वात्स्यायन ने कहा कि नौसेना हिंद महासागर में सक्रिय हर चीनी युद्धपोत, सर्वेक्षण जहाज और खुफिया पोत की गतिविधियों पर करीबी निगरानी रख रही है। भारत की नौसेना केवल देश की सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में सामरिक संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी निभा रही है। उन्होंने कहा, "भारत क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कोई भी देश अगर

स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तो जवाब तुरंत और निर्णायक होगा।" वाइस एडमिरल वात्स्यायन अंतरराष्ट्रीय फ्लोट रिज्यू, 'मिलन अभ्यास' और 'आईओएनएस चीफ्स कॉन्फ्लेव' की तैयारियों की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि यह आयोजन 18 फरवरी 2026 को विशाखापत्तनम में होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय नौसेना के बेड़े की समीक्षा करेंगी। इस अवसर पर स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रान्त और

कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियाँ भी अपने सामरिक कौशल का प्रदर्शन करेंगी। 55 देशों की भागीदारी तय, अमेरिका और रूस भी होंगे शामिल इस बार के आयोजन में अब तक 55 से अधिक देशों ने अपनी उपस्थिति की पुष्टि की है। इनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कई अन्य देशों के जहाज और प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। मिलन अभ्यास 20 से 25 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा,

जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास माना जा रहा है। भारतीय नौसेना इस वर्ष नवंबर में गुआम में होने वाले 'मालाबार अभ्यास' में भी हिस्सा लेगी। वाइस एडमिरल ने कहा कि इन अंतरराष्ट्रीय अभियानों से भारत की समुद्री क्षमता और रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सभी अंतरराष्ट्रीय गतिविधियाँ बिना किसी बाधा के जारी हैं।



श्री नरेन्द्र मोदी

माननीय प्रधानमंत्री

ई-नीलामी

माननीय मुख्यमंत्री को मिली

उपहार-स्मृति चिह्नों को खरीदने का गौरवपूर्ण अवसर

सभी लोग इस ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं



हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी

ई-नीलामी प्रक्रिया से प्राप्त धनराशि को कन्या शिक्षा पर किया जाएगा खर्च

उपहार-स्मृति चिह्नों की ई-नीलामी प्रक्रिया का होगा शुभारंभ

दिनांक: 9 से 30 नवंबर, 2024 तक

वेबसाइट <https://cmgujmento.gujarat.gov.in>

वेबसाइट पर निम्न वस्तुएँ देखी जा सकेंगी
उत्कृष्ट शिल्प, पारंपरिक उपहार, प्रादेशिक कलाकृतियाँ, स्वदेशी हस्तकला
स्मृति चिह्न जैसी अनेकों कीमती एवं सुंदर कलाकृतियाँ
नीलाम होने वाले उपहार-स्मृति चिह्नों की अधिक जानकारी के लिए <https://cmgujmento.gujarat.gov.in> पर जाएँ

माननीय मुख्यमंत्री को देश-विदेश से प्राप्त उत्कृष्ट भेंट व स्मृति चिह्नों की नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए



QR कोड को स्कैन करें

जन-जन के कल्याण के लिए वचनबद्ध गुजरात सरकार

आइए, सभी पोर्टल के माध्यम से इस गौरवमय ई-नीलामी में भाग लें

राजकोष, वित्त विभाग, गुजरात सरकार

कन्या शिक्षा के माध्यम से विकसित गुजरात और विकसित भारत के निर्माण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

- श्री हर्ष संघवी, माननीय उपमुख्यमंत्री, गुजरात

संपादकीय

चुनावी मौसम में सर्वेक्षण के गुणनाम सूत्र

देश के मौसम वैज्ञानिक भले ही भारत में मौसमों को सर्दी, गर्मी और बरसात तक सीमित बताते हैं, लेकिन वे एक और मौसम को रेखांकित करना भूल गए हैं— चुनाव का मौसम।

इस मौसम की खासियत यह है कि इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं होती। यह न तो पंचांग में दर्ज है, न मौसम विभाग इसकी भविष्यवाणी कर पाता है। यह मौसम केवल चुनाव आयोग की घोषणा के साथ आता है और मतदान संपन्न होते ही जैसे ही लौट जाता है, जैसे बरसात के बाद अचानक धूप निकल आए।

चुनाव घोषित होते ही सर्वेक्षणों की बहार शुरू हो जाती है। टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक, हर ओर आंकड़ों का अंबार लग जाता है। कभी कोई सर्वे, कभी कोई—जैसे कोई नया ट्रेंड चल पड़ा हो। अब सर्वेक्षण करवाना राजनीति का अभिन्न हिस्सा बन गया है। नेता और दल इन सर्वेक्षणों का सहारा लेकर अपनी टिकट सुनिश्चित करने या अपने ही दल के प्रतिद्वंद्वी की टिकट कटवाने तक की जुगत में लग जाते हैं। ये सर्वेक्षण कितने प्रामाणिक हैं, इसका कोई ठोस सबूत किसी के पास नहीं होता। सर्वेक्षण किसके द्वारा, कब और कैसे किए गए — इससे किसी को कोई मतलब नहीं।

इन सर्वेक्षणों से किसी उम्मीदवार को लाभ मिले या न मिले, लेकिन मतदाता जरूर भ्रमित हो जाता है। हर चैनल पर दिखाया जाने वाला अलग-अलग सर्वे मतदाता को इस कदर उलझा देता है कि वह तय ही नहीं कर पाता कि सच कौन बोल रहा है। हर सर्वे ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि झूठ भी सच लगने लगता है और सच केवल आंकड़ों के नीचे दबकर रह जाता है। कहने को तो सर्वेक्षण जनता की राय पर आधारित होते हैं, लेकिन यह 'जनता' कौन है — यह कोई नहीं बताता। कभी यह जनता कॉफी शॉप में बैठी मिलती है तो कभी सोशल मीडिया की टिप्पणियों में।

जनता से पूछा गया या नहीं, इसकी पुष्टि कभी नहीं होती, फिर भी परिणाम ऐसे दिए जाते हैं जैसे देश की तकदीर इन्हीं आंकड़ों से तय होगी। अब सवाल यह भी उठता है कि सर्वेक्षण कला है या विज्ञान? दरअसल, यह दोनों हैं। विज्ञान इसलिए कि जैसे हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, वैसे ही हर सर्वे का असर कहीं न कहीं दिखता है। और कला इसलिए कि इसे इतनी सजावट के साथ पेश किया जाता है कि झूठ भी आधा सच लगने लगता है। चुनावी मौसम की एक और खासियत यह है कि इसमें हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में राजनीतिक जानकार बन जाता है। चाय की दुकानों पर बैठे लोग आंकड़ों पर बहस करते हैं, रिक्शेवाला भी प्रतिशत की बात करता है, और पड़ोस के शर्मा जी तो ऐसे नतीजे सुनाते हैं, जैसे चुनाव आयोग उनके घर की छत पर बैठा हो। सच कहिए, अब पूरा देश एक बड़ा न्यूज स्टूडियो बन चुका है—हर कोई अपना चैनल चलाने में लगा है।

बिहार के चुनाव पर नेपाली निगाहें



सात सीमावर्ती जिले बिहार के हैं, जिनके मुख्यालय की राजनीतिक गतिविधियों में नेपाल के लोगों की दिलचस्पी बनी रहती है। चुनावी सभा चाहे दरभंगा में हो, या कि मोतिहारी में, राहुल-मोदी अथवा अमित शाह को देखने नेपाल के लोग पहुंच ही जाते हैं। बिहार में इस तरह के 60 से 65 जिले हैं, जिनके भावी विधायकों, मंत्रियों, सांसदों के 'गुड लुक' में बने रहने की कवायद नेपाल में चलती रहती है।

प्रेरणा

स्वदेशी का गर्व : डॉ. कलाम का अद्भुत उपहार जिसने भारत की पहचान को विश्व पटल पर

भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले और करोड़ों भारतीयों के प्रेरणास्रोत डॉ. ए.पी. जे. अब्दुल कलाम केवल वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि स्वदेशी भावना के सच्चे प्रतीक थे। वे मानते थे कि किसी देश की वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब वह अपने ज्ञान, अपने संसाधनों और अपनी तकनीक पर विश्वास करे। इसी सोच से जुड़ा एक प्रेरक प्रसंग उनके जीवन का वह अध्याय है जब उन्होंने पोलियोग्रस्त बच्चों के जीवन को सरल और सम्मानजनक बनाने के लिए एक अगोचर प्रयोग किया।

यह वह समय था जब भारत में पोलियो से प्रभावित बच्चों को भारी-भरकम लोहे के कैलिपर पहनने पड़ते थे। ये कैलिपर इतने वजनी होते थे कि बच्चे चल तो पाते थे, लेकिन हर कदम मानो उनके लिए एक परीक्षा होता था। इस समस्या को देखकर डॉ. कलाम का मन विचलित हुआ। उन्होंने ठान लिया कि वे इन बच्चों के लिए कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनके जीवन में सहजता और आत्मविश्वास लौट आए। उन्होंने तीन प्रमुख संस्थानों — रक्षा

अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO), ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी — के साथ मिलकर एक नई खोज की दिशा में काम शुरू किया। महीनों के अथक परिश्रम और प्रयोगों के बाद उन्होंने कार्बन कंपोजिट सामग्री से बने हल्के कैलिपर तैयार किए। इन कैलिपरों का वजन पारंपरिक कैलिपर की तुलना में लगभग दस गुना कम था, जिससे पोलियोग्रस्त बच्चे आसानी से चलने, दौड़ने और खेलने लगे।

जब यह नवाचार सफल हुआ, तो पूरे देश में डॉ. कलाम के इस प्रयास की चर्चा होने लगी। एक दिन प्रेस वार्ता में एक पत्रकार ने उनसे कहा, "सर, आपने स्वदेश में हल्के कैलिपर का निर्माण करके पूरे विश्व के सामने भारत का सिर ऊंचा कर दिया है।" तभी दूसरा पत्रकार बोला, "भारत अब आत्मनिर्भर बन गया है और स्वदेश में ही अनेक तकनीकों का निर्माण कर सकता है।"

डॉ. कलाम मुस्कराए — वह मुस्कान जो हमेशा उनके चेहरे पर ज्ञान और विनम्रता का संगम बनकर चमकती थी। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, "मैं तो स्वयं यह कहता हूँ कि हमारे पास आश्चर्यजनक सफलताओं का पूरा इतिहास है। भारत प्रारंभ से ही विश्वगुरु के रूप में प्रसिद्ध रहा है। हमारा भारत हर चीज में अग्रणी है। गेहूँ और चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। दूध के उत्पादन में पहला स्थान है। दूरसंचार उपग्रह के विकास में हम अग्रणी हैं। हमारी सभ्यता, संस्कृति और इतिहास लाजवाब है। हमें हर स्वदेशी सफलता पर गर्व करना चाहिए।"



का कॉन्सेप्ट इन्हीं वजहों से शुरू होता है। लामभाग हर तीसरे-चौथे परिवार की रिश्तेदारी नेपाल में दिखाई देती है। चूंकि, जब नेपाल में चुनाव होता है, भारत वाले दोस्त, रिश्तेदार एक्टिव हो जाते हैं, उसी तरह जब भारत के इन पांच राज्यों में चुनाव होता है, नेपाल का सरोकार सामने आ जाता है।

लेकिन, चुनावी दायरा 21 विधानसभा क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। ऐसे सात सीमावर्ती जिले बिहार के हैं, जिनके मुख्यालय की राजनीतिक गतिविधियों में नेपाल के लोगों की दिलचस्पी बनी रहती है। चुनावी सभा चाहे दरभंगा में हो, या कि मोतिहारी में, राहुल-मोदी अथवा अमित शाह को देखने नेपाल के लोग पहुंच ही जाते हैं। बिहार में इस तरह के 60 से 65 जिले हैं, जिनके भावी विधायकों, मंत्रियों, सांसदों के 'गुड लुक' में बने रहने की कवायद नेपाल में चलती रहती है।

दूसरा, मुस्लिम फैक्टर भी है, लगभग 80 फीसद मुस्लिम आबादी तराई क्षेत्र में है, शेष 20 प्रतिशत मुसलमान मुख्यतः काठमांडू, गोरखा और पश्चिम नेपाल की पहाड़ियों तक सीमित हैं। लेकिन, जो बॉर्डर लाइन के नेपाली मुसलमान हैं, बताना अब जरूरी नहीं रह गया, कि बिहार में होने वाले चुनाव में जो किसकी जीत के खाहिशमंद हैं। आप देख सकते हैं, चम्पारण के ढाका तथा सीमांचल के चार जिले पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज वाले अल्पसंख्यकों का रास्ता, नेपाल में एक्टिव मुसलमानों से रहता है।

बिहार-नेपाल व्यापार के लिए बारा, पर्सा, महोत्तरी, मोरंगा, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, सुनसरी और झापा जिलों से जुड़े 10 ट्रांजिट पॉइंट शामिल हैं। मुख्य व्यापार में कृषि उत्पाद, दूध प्रसंस्करण, नॉन-वोवन बैग निर्माण, पशुधन के लिए खनिज और विटामिन मिश्रण वाला उत्पादन, औषधि, पेट्रोलियम, लिथियम आयन सौर बैटरी, कोस्मेटिक्स से लेकर कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक

सामान तक शामिल हैं। लेकिन अब इसमें नया तड़का लगा है, शराब और शबाब का, जिसने एक नई किस्म की कनेक्टिविटी दोनों देशों में पैदा की है।

वर्ष 2016 में बिहार में शराबबंदी होने के बाद से, नेपाल के सीमावर्ती शहरों में अल्कोहल इंडस्ट्री और उसका खुदरा कारोबार जबरदस्त रूप से उभार पकड़ने लगा है। नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में होटल और रेस्टोरेंट भारतीय विजिटर्स की वजह से गुलजार हैं। बॉर्डर पार करके शराब पीने का शगल कुछ नया नहीं था। लेकिन इन दिनों आप वीरगंज से लेकर बिराटनगर, इटहरी और राजबिराज जैसे शहरों को जाकर देख आइये, चुनाव के समय शराब की मांग डबल हो गई है।

नौ वर्षों में नेपाल, बिहार वालों के लिए 'लीकर डेस्टिनेशन' बन चुका है। अब चूंकि, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, उनके समर्थकों को 'अतिरिक्त ऊर्जा' चाहिए, तो नेपाली शहरों में शराब का धंधा और तेज हुआ है, विदेशों से शराब का आयात 12 फीसद बढ़ गया। नेपाल की शराब लॉबी चाहती है, कि बिहार में वैसी सरकार रहे, जो मद्यनिषेध जारी रखना चाहती हो। शराबबंदी से पहले बिहार में 3,142 करोड़ की सालाना आमदनी केवल शराब के ठेकों से सरकार को होती थी। अब आप मानकर चलें, विगत नौ वर्षों में लगभग 30 हजार करोड़ का राजस्व नेपाल सरकार गया, मगर बिहार में शराबबंदी कामयाब नहीं हुई।

बिराटनगर के व्यापारी बताते हैं, 'बिहार सरकार द्वारा शराब पर बताने के बाद शराब की खपत बढ़ गई है। पहले हर दिन करीब सौ-डेढ़ सौ भारतीय शराब पीने के लिए हमारे इलाके में आते थे, अब यह

मुस्कान लौट आई। यह कहानी केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि की नहीं, बल्कि उस स्वदेशी भावना की है जिसने भारत को आत्मविश्वास दिया, यह एहसास दिलाया कि हम किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। डॉ. कलाम का जीवन हमें यह सिखाता है कि जब विज्ञान करुणा से जुड़ता है, तब वह समाज में बदलाव की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है।

आज जब भारत 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसे अभियानों की ओर बढ़ रहा है, तब डॉ. कलाम की यह स्वदेशी भावना पहले से भी अधिक प्रासंगिक हो उठी है। उनकी प्रेरणा से हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि देश की असली ताकत बाहरी संसाधनों में नहीं, बल्कि अपने लोगों की प्रतिभा, अपने वैज्ञानिकों के ज्ञान और अपने समाज के सामूहिक संकल्प में है।

डॉ. कलाम ने यह साबित किया कि स्वदेशी केवल उत्पाद नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा है। यही वह भावना है जो भारत को फिर से विश्वगुरु बनाने की दिशा में ले जा सकती है। यही है सच्चा 'स्वदेशी का गर्व'।

संख्या अचानक से डबल हो गई। रेस्टोरेंट के अलावा, होटलों को भी फायदा हुआ है, क्योंकि कुछ भारतीय रात भर रुकते हैं। वे शराब पीकर बॉर्डर पार बिहार नहीं जा सकते।

एक स्थानीय बिजनेसमैन बताते हैं, 'अमीर भारतीय महंगे होटलों में रुकते हैं, जबकि कम आय वाले लोग सस्ते होटलों में जाते हैं।' कोसी बैराज, कुनौली बाजार और सखाड़ा जैसे इलाकों में शराब बूढ़ रहे भारतीयों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। वहीं दूसरी ओर, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जैसे बिहार के बड़े शहरों से भी लोग राजबिराज, वीरगंज और नेपाल के दूसरे सीमावर्ती शहरों में आते हैं। चुनाव के समय पेटी भर-भर के बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है।

'पीपुल टू पीपुल कनेक्टिविटी' का दूसरा उदाहरण बिहार में कुकुरमुते की तरह उग आई अकिंस्ट्रा पार्टी है। उनमें दुमके लगाने वाली अधिकांश बालाएं नेपाल से मंगाई जाती हैं। सामाजिक-धार्मिक उत्सव हो, अथवा चुनाव, नेपाल से आई 'भोजपुरी डांस कलाकार' नेताओं के प्रचार और मनोरंजन के काम आ रही हैं। नेपाली डांसर बताती हैं, 'हमें राजनीतिक कार्यकर्ताओं के मनोरंजन के लिए जाना पड़ता है।' बिहार की राजनीति में रौनक लाने के वास्ते अश्विनी शाही, बन्दना नेपाल जैसी भोजपुरी डांसरों का मांग बढ़ गई है। मीडिया वाले भोजपुरी गानों और डांस में अश्लीलता पर सवाल पूछते हैं, नेता मुंह घुमा लेते हैं, अथवा सवाल इग्नोर कर देते हैं। किसी भी पार्टी के एजेंडे में अश्लीलता पर रोक का प्रण नहीं पायेगा। बिहार में यदि सचमुच गरीबी और बेरोजगारी है, तो ये सब धंधा कल कैसे रहा है?

सरदार पटेल की विरासत संजोते मोदी, राजनीतिक यात्रा और शासन के सिद्धांतों की झलक

भारत को जब 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, तब अंग्रेज एक खंडित उपमहाद्वीप छोड़ गए। विभाजन के आघात के साथ-साथ 560 से अधिक रियासतें भी थीं, जिनमें से प्रत्येक के अपने शासक थे। नवस्वतंत्र राष्ट्र ने खुद को एक दोराहे पर पाया। एकता के अभाव में कठोर मेहनत से प्राप्त स्वतंत्रता खोखली हो गई। ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर एक व्यक्ति ने चुनौती स्वीकार की और वे थे सरदार वल्लभभाई पटेल-देश के पहले उपप्रधानमंत्री और गृह मंत्री।

दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प और अदम्य इच्छाशक्ति के साथ उन्होंने इन रियासतों को एक राष्ट्र में मिलाया, जिससे स्वतंत्र भारत को उसका आकार और शक्ति मिली। राष्ट्र को एकीकृत करने वाले इस महान व्यक्तित्व के अद्वितीय प्रयासों को वह मान्यता नहीं मिली, जिसके वे वास्तव में हकदार थे। दशकों बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस विरासत को संरक्षित करने तथा उसका सम्मान करने के लिए निर्णायक कदम उठाए।

नरेन्द्र मोदी की राजनीतिक यात्रा और शासन के सिद्धांतों से सरदार पटेल के प्रभाव साफ दिखते हैं। वे पटेल को 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के अपने दृष्टिकोण के पीछे का पथप्रदर्शक मानते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सरदार पटेल की विरासत को सार्थक कार्यों के माध्यम से सम्मानित किया। उन्होंने अहमदाबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक का जीर्णोद्धार कराया तथा उसे एक प्रमुख संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र में परिवर्तित किया।

सरदार पटेल को पटेल जयंती पर मोदी ने युवाओं को उनके योगदान के बारे में जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने शुरू किए। इनमें एकता यात्रा राष्ट्रीय एकत्व की भावना को बढ़ावा देने के एक सशक्त मंच के रूप में उभरी। सरदार पटेल के प्रति मोदी की श्रद्धा के सबसे प्रभावशाली प्रतीक के रूप में गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर स्टैच्यू आफ यूनिटी स्थापित हुई। मुख्यमंत्री मोदी द्वारा परिकल्पित और 31 अक्टूबर, 2018 को प्रधानमंत्री के रूप में उनके द्वारा अनावृत यह प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी 182 मीटर की ऊंचाई प्रतीकात्मक रूप से गुजरात के 182 विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है।

मोदी ने इस प्रतिमा के निर्माण में पूरे देश को शामिल करने के लिए 'लोहा अभियान' शुरू किया, जिसमें देश के छह लाख से अधिक गांवों के किसानों ने लोहे के औजार दान किए। इस अभियान ने राष्ट्रीय एकता की भावना को मूर्त रूप दिया। स्टैच्यू आफ यूनिटी के निर्माण के दौरान प्रांथिक डिजाइन में सरदार पटेल को कुतू-पायजामा पहने दिखाया गया था। मोदी ने इस पर बल दिया कि प्रतिमा

में वे धोती पहने हुए हों, जैसे किसान पारंपरिक रूप से पहनते हैं। इससे एक बड़ी चुनौती उत्पन्न हुई, क्योंकि ऊंची प्रतिमाओं का आधार आमतौर पर चौड़ा बनाया जाता है। फिर भी मोदी ने यह सुनिश्चित किया कि पटेल की पोशाक में कोई बदलाव किए बिना हरमभव उपाय किए जाएं, क्योंकि उनका मानना था कि सरदार पटेल देश के किसानों के प्रतीक हैं।

सरदार पटेल के अधूरे सपनों में से एक सरदार पटेल बांध परियोजना मुख्यमंत्री मोदी के प्रयासों से साकार हुई। पटेल इस परियोजना की कल्पना गुजरात की बिजली-पानी संबंधी चुनौतियों के समाधान के रूप में कर रहे थे। दशकों तक बांध की ऊंचाई बढ़ाने के विरोध के कारण यह अपनी पूरी क्षमता हासिल नहीं कर सकी। मुख्यमंत्री मोदी ने इस परियोजना को पूरा करने का संकल्प लिया। इस परियोजना ने गुजरात के पटेल की विरासत को संरक्षित करने तथा उसका सम्मान करने के लिए निर्णायक कदम उठाए।

आज जब मोदी के नेतृत्व में निर्मित नहरों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से नर्मदा का पानी गुजरात के प्रत्येक गांव तक पहुंच रहा है, तो यह उस सपने की पूर्ति के रूप में सामने आता है, जिसकी कल्पना पटेल ने दशकों पहले की थी। सरदार पटेल द्वारा परिकल्पित सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण पूरे भारत में तीर्थस्थलों के विकास के लिए एक मार्गदर्शक माडल बना। मुख्यमंत्री के रूप में मोदी ने सरदार पटेल की ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के लिए कई पहलों का नेतृत्व किया।

सरदार पटेल का राजनीतिक रूप से एकीकृत भारत का सपना जम्मू-कश्मीर के मामले में साकार नहीं हो सका था। पटेल हमेशा चाहते थे कि जम्मू-कश्मीर को भारत में पूरी तरह मिला दिया जाए, टीक उसी तरह जैसे उन्होंने अन्य रियासतों को मिलाया। जम्मू-कश्मीर के सबसे प्रभावशाली प्रतीक के रूप में गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर स्टैच्यू आफ यूनिटी स्थापित हुई। मुख्यमंत्री मोदी द्वारा परिकल्पित और 31 अक्टूबर, 2018 को प्रधानमंत्री के रूप में उनके द्वारा अनावृत यह प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी 182 मीटर की ऊंचाई प्रतीकात्मक रूप से गुजरात के 182 विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है।

मोदी ने इस प्रतिमा के निर्माण में पूरे देश को शामिल करने के लिए 'लोहा अभियान' शुरू किया, जिसमें देश के छह लाख से अधिक गांवों के किसानों ने लोहे के औजार दान किए। इस अभियान ने राष्ट्रीय एकता की भावना को मूर्त रूप दिया। स्टैच्यू आफ यूनिटी के निर्माण के दौरान प्रांथिक डिजाइन में सरदार पटेल को कुतू-पायजामा पहने दिखाया गया था। मोदी ने इस पर बल दिया कि प्रतिमा

अभियान

चार महीने बाद योगनिद्रा से जागेंगे भगवान विष्णु: देव उठानी एकादशी पर फिर आरंभ होंगे शुभ

हिंदू धर्म की मान्यताओं में एकादशी तिथि का अत्यंत विशेष स्थान है, और उनमें भी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को सबसे पवित्र माना गया है। यही वह दिन है जब भगवान विष्णु अपनी चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं। इसे "देवउठनी एकादशी" या "प्रबोधिनी एकादशी" कहा जाता है। माना जाता है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शय्या पर विश्राम करने चले जाते हैं, और ठीक चार महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागकर पुनः सृष्टि के पालन का कार्य आरंभ करते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है, जो भक्ति, साधना और संयम का काल माना जाता है।

इस वर्ष कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 11 नवंबर 2025 को सुबह 9 बजकर 11 मिनट से शुरू होकर 2 नवंबर को सुबह 7 बजकर 31 मिनट तक रहेगी। पंचांग के अनुसार व्रत 1 नवंबर को ही



रखा जाएगा। यह दिन न केवल भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक है, बल्कि समस्त शुभ और मांगलिक कार्यों के पुनः आरंभ का संकेत भी है। चार महीनों तक विवाह, गृहप्रवेश, मुंडन, उपनयन और अन्य मांगलिक कार्यों पर रोक मानी जाती है। लेकिन देवउठनी एकादशी के दिन से यह निषेध

समाप्त हो जाता है और जीवन के सभी शुभ कार्यों के लिए द्वार पुनः खुल जाते हैं। इस दिन पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब भगवान विष्णु योगनिद्रा में जाते हैं, तब ब्रह्माण्ड के समस्त देवता भी विश्राम अवस्था में चले जाते हैं। इस समय भक्ति, तप, जप और व्रत का महत्त्व बढ़ जाता है। देवउठनी एकादशी के

दिन भगवान विष्णु का पूजन तुलसी और शालिग्राम के साथ करने की परंपरा है। इस दिन तुलसी विवाह का उत्सव भी मनाया जाता है, जो भगवान विष्णु और तुलसी माता के दिव्य मिलन का प्रतीक है। माना जाता है कि इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन करने से जीवन में वैवाहिक सुख, समृद्धि

और शांति आती है। इस वर्ष देवउठनी एकादशी पर अद्भुत योग बन रहे हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, इस दिन ब्रह्म योग, शुभ कर्म योग और सिद्धि योग जैसे संयोगों का निर्माण होगा, जो विशेष रूप से वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों के लिए अत्यंत लाभकारी रहेंगे। इन राशियों के जातकों के लिए धन, सौभाग्य और सफलता के नए अवसर खुल सकते हैं। ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि भगवान विष्णु की विशेष कृपा इन जातकों पर बनी रहेगी और उनके जीवन में रुकावटें दूर होंगी।

देवउठनी एकादशी का यह पर्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन श्रद्धालु रात्रि में दीपदान करते हैं, भजन-कीर्तन गाते हैं और भगवान विष्णु का जागरण करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन व्रत रखकर और भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति

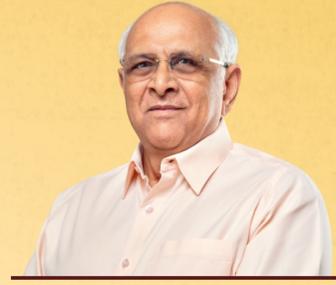
होती है। भक्तजन इस दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, भगवान विष्णु के समक्ष दीपक प्रज्वलित करते हैं, तुलसी दल अर्पित करते हैं और मंत्रों का उच्चारण करते हुए प्रार्थना करते हैं—

“ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः”। यह माना जाता है कि इस मंत्र के जप से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और साधक को सुख, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं।

देवउठनी एकादशी का यह पर्व हमें यह संदेश देता है कि जैसे भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागकर सृष्टि के कार्यों में पुनः प्रवृत्त होते हैं, वैसे ही हमें भी अपने भीतर की जड़ता और आलस्य से जागकर जीवन के शुभ कार्यों में लग जाना चाहिए। यह दिन भक्ति, जागृति और आत्मबोध का प्रतीक है। इसीलिए इसे केवल एक व्रत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पुनर्जागरण का उत्सव माना जाता है।



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



श्री भूपेन्द्रभाई पटेल
माननीय मुख्यमंत्री, गुजरात

“एक भारत श्रेष्ठ भारत” के गौरव का महोत्सव भारत पर्व २०२५

भारत की विविध संस्कृतियों, कला और व्यंजनों का अद्भुत समन्वय एक ही स्थान पर!

विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा - स्टेच्यू ऑफ युनिटी, राष्ट्रीय उत्सव का केंद्र बनेगी, क्योंकि यहाँ एकतानगर में “एक भारत श्रेष्ठ भारत” के अंतर्गत 'भारत पर्व २०२५' का भव्य आयोजन किया गया है। यह महोत्सव थीम पवेलियन, क्षेत्रीय व्यंजनों, पारंपरिक हस्तशिल्प और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साझा मंच प्रदान करेगा, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता में उसकी अटूट एकता को प्रतिबिंबित करेगा।



भारत पर्व २०२५

१ से १५ नवंबर, २०२५

सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ

डैम व्यू पॉइन्ट-1,
वैली ऑफ फ्लावर के सामने

थीम पवेलियन

फूड स्टॉल्स

क्राफ्ट स्टॉल्स

जंगल सफारी के पास

अन्य आकर्षण

लेज़र, लाइट और साउंड शो • जंगल सफारी और डायनो ट्रेल • सरदार सरोवर डेम और बोटिंग • कैक्टस गार्डन
बटरफ्लाई गार्डन • आरोग्य वन • चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क • विश्व वन

स्टैच्यू ऑफ युनिटी, एकतानगर

'भारत पर्व' माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में “एक भारत श्रेष्ठ भारत” की राष्ट्रीय शक्ति का जीवंत संदेश है।

श्री हर्ष संघवी, माननीय उपमुख्यमंत्री, गुजरात

